स्थापना : 1997 - संपर्क : 09869256875

प्रत्येक महीने की 1ली और 16वीं तारीख एवं दिन को प्रकाशित

• Website : www.railsamachar.com
• Website : www.railsamacharenglish.com
• Email : railwaysamachar@gmail.com

# परिपूर्ण रेलवे समाचार

रेलवे का दोस्त, यात्रियों का साथी

■ वर्ष -15 ■ अंक - 351 ■ कल्याण (मुंबई), ■ 16 से 31 दिसंबर 2016 ■ पेज - 8 ■ मूल्य 5 रु.

## महाप्रबंधकों के रिक्त पदों पर एक साथ पोस्टिंग क्यों नहीं ?

सुरेश त्रिपाठी

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने 30 नवंबर, 2016 को दो महाप्रबंधकों की पोस्टिंग के

### एक महाभ्रष्ट जीएम को सीएलडब्ल्यू का अतिरिक्त चार्ज देने का औचित्य क्या था ?

डी. के. शर्मा, महाप्रबंधक, म.रे.

ऑर्डर जारी किए. इसमें से एस. एन. अग्रवाल, (आईआरएसई - 1982 बैच) को दक्षिण पूर्व रेलवे और डी. के. शर्मा (आईआरएसईई - 1982 बैच) को मध्य रेलवे का महाप्रबंधक बनाया गया है. श्री अग्रवाल और श्री शर्मा दोनों ही आउट स्टैंडिंग एवं ईमानदार अधिकारी हैं. श्री अग्रवाल इससे पहले पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत थे. इसके अलावा वह डीआरएम/नागपुर, द.पू.म.रे. भी रहे हैं, जहां उन्होंने अपनी एसीआर अपने मातहत ब्रांच अफसरों से लिखवाने का एक महत्वपूर्ण कार्य भी किया था, जिसके लिए उन्हें नागपुर में आज भी याद किया जाता है. इसके अतिरिक्त उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है. मृदुभाषी और मिलनसार स्वभाव वाले श्री अग्रवाल की ईमानदारी और प्रशासनिक क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है.

मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक डी. के. शर्मा भी इससे पहले पश्चिम रेलवे में ही मुख्य विद्युत अभियंता के रूप में कार्यरत थे. श्री शर्मा ने इससे पहले मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और कोंकण रेलवे में बतौर सीईई/मध्य रेलवे, सीईई/प्रोजेक्ट/कोंकण रेलवे, डीआरएम/नागपुर/म.रे., एडीआरएम/मुंबई/म.रे. सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है. श्री शर्मा को सामान्य प्रशासन सहित इलेक्ट्रिकल एसेट्स के निर्माण और प्रबंधन का गहन अनुभव शेष पेज 6 पर...

## पूर्वांचल की जनता की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई -रेलमंत्री

### एसी लोकोशेड, डोमिनगढ़-गोरखपुर-कैंट-कुसुम्ही तीसरी और नकहा दूसरी लाइन का शिलान्यास

**गोरखपुर ब्यूरो :** रेलमंत्री सुरेश प्रभु द्वारा रविवार, 18 दिसंबर को बांद्रा टर्मिनस स्टेशन, मुंबई से रिमोट द्वारा एवं सांसद महंत योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोरखपुर स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में गोरखपुर-गोंडा रेल खंड के विद्युतीकरण का लोकार्पण तथा गोरखपुर में 100 लोको क्षमता वाले एसी लोको शेड एवं डोमिनगढ़-गोरखपुर, गोरखपुर कैंट-कुसुम्ही तीसरी लाइन शेष पेज 7 पर...

## उ. प्र. में यात्री सुविधा के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जा रहे हैं -सुरेश प्रभु

### रेलमंत्री सुरेश प्रभु द्वारा बरेली में विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास

गोरखपुर ब्यूरो

**बरेली :** रेलमंत्री, सुरेश प्रभु ने रविवार, 11 दिसंबर को पूर्वोत्तर रेलवे के बरेली सिटी स्टेशन पर आयोजित समारोह में बरेली सिटी स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार एवं उन्नत यात्री सुविधाओं, इज्जतनगर मंडल शेष पेज 6 पर...

## समस्या पैदा करना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के समान है -यू.एस.झा

### चित्रकूट में आरपीएफ एसो. की कार्यकारिणी एवं जनरल काउंसिल की मीटिंग संपन्न

**चित्रकूट :** ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन (एआईआरपीएफए) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और जनरल काउंसिल की दो दिवसीय बैठक 26-27 नवंबर को चित्रकूट धाम में संपन्न हुई. बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष एस. आर. रेड्डी और राष्ट्रीय महामंत्री यू. एस. झा सहित राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं जनरल काउंसिल के सभी सदस्य उपस्थित थे. इस बैठक में तय एजेंडा के अनुसार कार्यवाही हुई और प्रशासन द्वारा एसोसिएशन के साथ किए जा रहे सौतेले व्यवहार सहित लंबे समय से रेलवे बोर्ड स्तर पर पीएनएम की बैठक न होने तथा रेलवे बोर्ड के आदेश का उल्लंघन करते हुए एसोसिएशन के जोनल पदाधिकारियों का अकारण और अनावश्यक ट्रांसफर किए जाने की सभी शेष पेज 5 पर...

### आरपीएफ एसोसिएशन की एजीएम नई दिल्ली में 7, 8, 9 जनवरी को

ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन की वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) 7,8,9 जनवरी को एस्टेट एंट्री, रोड स्थित एसोसिएशन के मुख्यालय परिसर में होगी. इस सभा में रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने अपनी उपस्थिति की मंजूरी प्रदान कर दी है. इसके अलावा रेल राज्यमंत्री सहित कई अन्य मंत्रियों और सांसदों के उपस्थित रहने की संभावना है. आरपीएफ एसोसिएशन, मध्य रेलवे जोन की वार्षिक बैठक 19-20 दिसंबर को साईंनगर शिर्डी में संपन्न हुई.

# प्रयागराज एक्सप्रेस में एलएचबी कोचों का प्रयोग

## सांसदों ने किया रेक का शुभारम्भ

### 24 से 22 कोच की हुई ट्रेन, एसी में 62 बर्थों की वृद्धि, स्लीपर की 64 बर्थें हो गईं कम

**इलाहाबाद :** रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों को बेहतर सुविधा देने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में इलाहाबाद से नई दिल्ली के बीच चलने वाली 12417 अप प्रयागराज एक्सप्रेस में रविवार,18 दिसंबर से नए एलएचबी रेक का इस्तेमाल शुरू किया गया है. इसका शुभारम्भ सांसद केशव प्रसाद मौर्य एवं श्यामाचरण गुप्त द्वारा किया गया. दोनों सांसदों ने इलाहाबाद की पहचान प्रयागराज एक्सप्रेस के नए एलएचबी रेक मे परिवर्तन पर बधाई दी और रेल प्रशासन को यात्रियों को नई सुविधा के लिए साधुवाद दिया.

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक संजय कुमार पंकज ने सांसदों एवं अतिथियों का स्वागत करते हुए मंडल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि प्रयागराज एक्सप्रेस उत्तर मध्य रेलवे ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण गाड़ियों में से एक है, यह बहुत ही लोकप्रिय गाड़ी है. उन्होंने कहा कि 1984 से इसके प्रारम्भ होने के बाद से लगातार इस गाड़ी को यात्रियों के लिए अधिक से अधिक सुविधाजनक तथा तकनीकी रुप से अप-ग्रेड किया जाता रहा है. इसमें लगाए गए नए एलएचबी कोच, पुराने कोचों से ज्यादा हल्के और लम्बे हैं, इससे बिजली की खपत में कमी होगी, साथ ही हर कोच में पहले से अधिक संख्या में यात्री यात्रा कर पाएंगे. यह कोच 160 किमी. प्रति घंटे की गति से चलने के लिए फिट हैं. स्टील की हल्की लेकिन मजबूत बॉडी होने के कारण इनमें तेज गति से चलने के दौरान आवाज और कंपन काफी कम होता है.

उन्होंने बताया कि एलएचबी रेक के वातानुकूलित कोचों में अच्छी. एयरकंडीशनिंग होने के साथ ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी है. प्रकाश व्यवस्था भी पुराने कोचों से बेहतर है. प्रयागराज एक्सप्रेस में अब तक फर्स्ट एसी-1, सेकेंड एसी-3, थ्री एसी-4, स्लीपर-12, जनरल-2, एसएलआर-2 सहित कुल 24 कोच लगते थे, लेकिन नए एलएचबी कोचों की लंबाई अधिक होने के कारण अब इसमें कोचों की संख्या इस प्रकार होगी- फर्स्ट एसी-1, सेकेंड एसी-3, थ्री एसी-4, स्लीपर-10, जनरल-2, एसएलआर-2 सहित कुल 22 कोच हैं. नए एलएचबी कोचों के फर्स्ट एसी में 24 बर्थ, सेकेंड एसी में 54 बर्थ, थ्री एसी में 72 बर्थ तथा स्लीपर में 80 बर्थ की व्यवस्था है. इस एलएचबी रेक के फर्स्ट एसी कोच में 6 बर्थ, सेकेंड एसी में 24 बर्थ, थ्री एसी में 32 बर्थ की बढ़ोत्तरी हुई है तथा स्लीपर कोच में 64 बर्थें कम हो गई हैं. इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक ए. के. द्विवेदी, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक बी. के. मिश्रा, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक अंशू पांडेय, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियन्ता अजीत कुमार सिंह, वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियन्ता नीरज यादव, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियन्ता अमिताभ शर्मा, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी वी. के. गौतम, वरिष्ठ मंडल अभियन्ता सुनील कुमार गुप्ता, वरिष्ठ मंडल अभियन्ता आई.पी.एस. यादव, मंडल वाणिज्य प्रबंधक पी. पी. लाठे एवं पी. के. शर्मा, स्टेशन प्रबंधक राजाराम राजपूत सहित मंडल के अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं जनसमूह उपस्थित था.

## शाहदरा-सहारनपुर बाईपास सेक्शन के दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण का शिलान्यास

**शाहदरा-शामली-टपरी-सहारनपुर बाईपास रेल सेक्शन के दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण का शिलान्यास मंगलवार, 20 दिसंबर रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा द्वारा किया गया. इस अवसर पर दिल्ली मंडल, उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक अरुण अरोरा सहित मंडल के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे.**

# रेलवे सेफ्टी टास्क फोर्स की पहली बैठक

### भारतीय रेल परिवहन को संरक्षित एवं सुरक्षित बनाने हेतु विभिन्न उपायों पर हुई चर्चा



**उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय रेलवे सेफ्टी टास्क फोर्स की बैठक को संबोधित करते उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक और टास्क फोर्स के अध्यक्ष अरुण सक्सेना. उनके साथ हैं टास्क फोर्स के समन्वयक मध्य रेलवे के मुख्य संरक्षा अधिकारी शुभ्रांशु एवं महाप्रबंधक के सचिव अमित मिश्रा और सदस्य जॉन थॉमस, एस. अनन्थरामन और सतीश कुमार.**

**इलाहाबाद :** भारतीय रेल को सुरक्षित एवं संरक्षित बनाने की दृष्टि से रेलमंत्री सुरेश प्रभु के निर्देश पर एक उच्चस्तरीय रेलवे सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया गया है. इस टास्क फोर्स का अध्यक्ष उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अरुण सक्सेना को बनाया गया है. इस टास्क फोर्स के समन्वयक मध्य रेलवे के मुख्य संरक्षा अधिकारी शुभ्रांशु हैं. इसके सदस्य दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्य विद्युत अभियंता जॉन थॉमस और दक्षिण रेलवे के मुख्य परिचालन प्रबंधक एस. अनंतरामन तथा पूर्व रेलवे के अपर महाप्रबंधक सतीश कुमार हैं.

इस संरक्षा समिति का मुख्य कार्य इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट, फील्ड इंटरव्यू आदि विभिन्न माध्यमों से सही आकड़ों को एकत्रित करना, रेल परिचालन से जुड़े सभी क्षेत्रों में से चार से पांच ऐसे सुझाव देना, जिनको प्रभावी बनाकर संरक्षा को और बेहतर बनाया जा सके, तथा उन सुझावों को यथार्थ रूप में लाने के लिए कार्य-योजना बनाना है. इस संरक्षा समिति की पहली बैठक मंगलवार, 12 दिसंबर 2016 को उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय, सुबेदारगंज, इलाहाबाद में आयोजित हुई. इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे अरुण सक्सेना ने की.

इस बैठक में संरक्षा समिति के उपरोक्त सभी सदस्य उपस्थित थे. बैठक के दौरान भारतीय रेल परिवहन को संरक्षित बनाने के लिए किए गए कार्यों पर चर्चा की गई. इस अवसर पर उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य संरक्षा अधिकारी, मुख्य परिचालन प्रबंधक, मुख्य विद्युत अभियंता, मुख्य यांत्रिक अभियंता, मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार अभियंता, प्रमुख मुख्य अभियंता, विद्युत सलाहाकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, मुख्य कार्मिक अधिकारी एवं भंडार नियंत्रक द्वारा पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से अपने-अपने विभागों के संबंध में संरक्षा में सुधार से संबंधित सुझावों का विवरण उच्चस्तरीय रेलवे सेफ्टी टास्क फोर्स के सम्मुख रखा गया. संरक्षा समिति द्वारा इन प्रस्तावित सुझावों में से क्रियान्वित किए जाने वाले सुझावों का चयन करके उन्हें अपनी रिपोर्ट में समाहित किया जाएगा. बैठक के दौरान स्टाफ की आपूर्ति, रेलकर्मियों के लिए रिफ्रेशर/प्रमोशनल कोर्सेस, उन्नत तकनीकों का प्रयोग, गहन निरीक्षण, ट्रेनिंग को और बेहतर बनाने आदि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया. इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक वाई. पी. सिंह, मुख्य कार्मिक अधिकारी ओम प्रकाश, मुख्य परिचालन प्रबंधक अनुराग सहित अन्य सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे.

# हजारीबाग-बरकाकाना नई रेलवे लाइन का उद्घाटन

**रांची :** रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने हजारीबाग-बरकाकाना नई रेलवे लाइन का रेल भवन, नई दिल्ली से ऑनलाइन उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि 203 किमी. लंबी कोडरमा-रांची रेलवे लाइन भी जल्दी ही पूरी होने वाली है. इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास भी उपस्थित थे. झारखंड सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नई दिल्ली में रेल भवन में रेलमंत्री सुरेश प्रभु और झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने नवनिर्मित हजारीबाग-बरकाकाना रेलवे लाइन का उद्घाटन



**203 किमी. लंबी कोडरमा-रांची रेलवे लाइन भी जल्दी ही पूरी होगी**

किया. इस अवसर पर दोनों ने हजारीबाग से कोडरमा तक चलने वाली पैसेंजर गाड़ी को बरकाकाना तक के लिए विस्तारित कर हरी झंडी भी दिखाई.

इस अवसर पर रेल भवन से संबोधित करते हुए रेलमंत्री प्रभु ने कहा कि 203 किमी. लंबी बहुप्रतीक्षित रांची - कोडरमा रेलवे लाइन भी लगभग तैयार हो चुकी है और बहुत शीघ्र ही उसका भी उद्घाटन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि फरवरी, 2015 में प्रधानमंत्री ने स्वयं हजारीबाग-कोडरमा रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था. उसी का परिणाम है कि आज महज डेढ़ वर्ष में यह लाइन बरकाकाना तक पहुंच गई है. मुख्यमंत्री रघुबर दास ने इस अवसर पर केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए राज्य के लिए अनेक अन्य ट्रेनों की मांग भी की.

# 15 साल से एक जगह बैठे अनिल गुप्ता को हटाने की मांग

सुरेश त्रिपाठी

- संदिग्ध पुराने रिकाड्र्स एवं क्रेडेंशियल वाले कॉन्ट्रैक्टर्स/लाइसेंसीज को पैंट्री कारों का आवंटन
- अनिल गुप्ता द्वारा उगाही गई अवैध धनराशि का पंजाब में रिश्तेदारों के नाम बेनामी निवेश?
- जेजीएम/आईआरसीटीसी अनिल गुप्ता के पूरे सेवाकाल की गोपनीय जांच कराए जाने की मांग
- किसी अधिकारी को सालों एक जगह पदस्थ रखना नियम विरुद्ध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (आईआरसीटीसी) मुख्यालय, नई दिल्ली में एक ही जगह पिछले 15 सालों से बैठे जॉइंट जनरल मैनेजर (जेजीएम) अनिल गुप्ता को अन्यत्र ट्रांसफर किए जाने की मांग की गई है. 2 दिसंबर 2016 को रेलमंत्री सुरेश प्रभु को लिखे गए एक पत्र के मुताबिक श्री गुप्ता आईआरसीटीसी में वर्ष 2001 से अब तक लगातार एक जगह पदस्थ हैं और वह तमाम मोबाइल लाइसेंसीज की परेशानी का सबब बन गए हैं. इससे आईआरसीटीसी की साख की धक्का लग रहा है. पत्र के मुताबिक श्री गुप्ता लाइसेंसीज को कई तरह से परेशान कर रहे हैं और मोबाइल कैटरिंग में अपने नए/पुराने चहेते लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिनकी योग्यताएं संदिग्ध हैं, जिससे लगभग सभी पैंट्री कारों में घटिया स्तर के खाने की आपूर्ति और यात्रियों से जमकर ओवर चार्जिंग हो रही है.

पत्र के अनुसार आईआरसीटीसी में 15 साल से एक ही जगह जमे श्री गुप्ता मोबाइल कैटरिंग सर्विसेज (पैंट्री कार सर्विसेज) के आवंटन का कार्य देख रहे हैं. रेलमंत्री को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि अनिल गुप्ता की गतिविधियां अत्यंत संदिग्ध हैं और वे उन्हीं लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो उनके नजदीकी या जानकार हैं तथा ऐसे पुराने एवं नए कॉन्ट्रैक्टर्स अथवा लाइसेंसीज को पैंट्री कार आवंटन किया जा रहा है, जिनके क्रेडेंशियल और पुराने रिकार्ड्स संदिग्ध हैं. इस बारे में आईआरसीटीसी प्रशासन को भी बखूबी मालूम है. तथापि, इस प्रकार के लगभग सभी कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ उन्हीं कुछ नए/पुराने कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को आवंटित किए जा रहे हैं, जो कि अनिल गुप्ता के चहेते अथवा जानकार हैं. पत्र में यह भी कहा गया है कि इन संदिग्ध क्रेडेंशियल वाले कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स से अनिल गुप्ता को बड़े पैमाने पर अवैध धनराशि प्राप्त हुई है, जिसे उन्होंने पंजाब में अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम से बेनामी निवेश किया है.

पत्र में कहा गया है कि लंबे समय से एक जगह जमे रहने और भ्रष्ट गतिविधियों की वजह से अनिल गुप्ता ने आईआरसीटीसी में अपनी काफी मजबूत स्थिति बना ली है और अब वह आईआरसीटीसी की साख के लिए खतरा बन गए हैं. पत्र में अनिल गुप्ता के हवाले से यह भी कहा गया है कि चूंकि वह आईआरसीटीसी और रेलवे बोर्ड के प्रत्येक अधिकारी को अपनी तमाम सेवाओं से 'ओब्लाइज' करते रहते हैं, इसलिए उन्हें न तो कोई नुकसान पहुंचा सकता है, और न ही कोई उनके खिलाफ शिकायत कर सकता है. उल्लेखनीय है कि श्री गुप्ता को आईआरसीटीसी में पूर्व सीएमडी एम. एन चौपड़ा लेकर आए थे. उससे पहले वह रेलवे बोर्ड के ईडी/कैटरिंग के साथ करीब 15 वर्षों तक जुड़े रहे थे. दयाधार पर रेलवे में पहले गार्ड की नौकरी में आए श्री गुप्ता मेडिकली डिकैटेगराइज होकर उत्तर रेलवे के कमर्शियल विभाग में कमर्शियल इंस्पेक्टर बन गए थे, मगर उत्तर रेलवे में शायद ही उन्होंने कभी एकाध दिन काम किया होगा.

पत्र में लिखा गया है कि श्री गुप्ता कहते हैं कि आईआरसीटीसी में कई मैनेजिंग डायरेक्टर्स आए और गए, मगर वह वहीं हैं और अंत तक वहीं रहेंगे भी. पत्र में यह भी कहा गया है कि इससे पहले श्री गुप्ता का दो बार अन्यत्र ट्रांसफर किया गया था, मगर उन्होंने दोनों बार अपने उच्च संपर्कों के बल पर अपना ट्रांसफर रद्द करा लिया था. उसके बाद उनके उच्च संपर्कों के मद्देनजर किसी ने उनको उनकी जगह से हिलाने की फिर कभी कोई कोशिश भी नहीं की. ज्ञातव्य है कि श्री गुप्ता के पास न जाने ऐसी कौन सी जड़ी-बूटी है, जिसे सुंघाने के बाद कोई भी सीएमडी अथवा डायरेक्टर उन्हें अन्यत्र शिफ्ट किए जाने की सोचता भी नहीं है. जबकि उनकी वजह से न सिर्फ आईआरसीटीसी में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, बल्कि इस संबंध में कई लाइसेंसीज और कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा की गई तमाम शिकायतों के कारण इसकी साख को भी भारी नुकसान हुआ है.

पत्र में कहा गया है कि यदि अनिल गुप्ता को उनकी वर्तमान जगह से जल्दी नहीं हटाया जाता है, तो आईआरसीटीसी को विभागीय तौर पर मोबाइल कैटरिंग सर्विसेज को हैंडल कर पाना मुश्किल हो जाएगा और यहां वही पुराना लाइसेंस राज लगातार चलता रहेगा, जिससे न सिर्फ इस लाभ कमाने वाले सरकारी रेलवे उपक्रम को भारी नुकसान हो सकता है, बल्कि वर्तमान में मोबाइल कैटरिंग (पैंट्री कारों) में जो गुणवत्ताविहीन खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और ओवर चार्जिंग धड़ल्ले से हो रही है, उसका मुख्य कारण अनिल गुप्ता का भ्रष्टाचार और उनके द्वारा गलत लोगों को प्रोत्साहित किया जाना है. पत्र में रेलमंत्री से अनुरोध किया गया है कि इस पूरे मामले की गोपनीय जांच करवाई जाए और उससे पहले अनिल गुप्ता को दिल्ली जोन को छोड़कर किसी अन्य जोन में ट्रांसफर किया जाए, जिससे वह इस जांच को प्रभावित न कर सकें.

## आईआरसीटीसी की स्थापना को भी अब तक 15 साल नहीं हुए हैं -डॉ. ए. के. मनोचा

इस संदर्भ में जब 'रेलवे समाचार' ने आईआरसीटीसी के सीएमडी डॉ. ए. के. मनोचा को उनके मोबाइल पर संपर्क करके पूछा कि आखिर क्या कारण है कि अनिल गुप्ता को लगातार 15 साल से एक ही जगह बैठाए रखा गया है और इसके साथ ही सारे प्रमोशन भी उन्हें उनकी पोस्ट को अपग्रेड करते हुए एक ही जगह पर दिए गए हैं? इस पर डॉ. मनोचा ने सिर्फ यह कहकर बात समाप्त कर दी कि 15 साल तो अभी आईआरसीटीसी की स्थापना को भी नहीं हुए हैं. उल्लेखनीय है कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट का 'कॉर्पोरेट प्रोफाइल' पेज खुद इस बात का गवाह है कि आईआरसीटीसी की स्थापना 27 सितंबर 1999 को हुई थी. तब शायद डॉ. मनोचा रेलवे में अपने शैशवकाल में रहे होंगे. इस तरह आईआरसीटीसी के गठन को अब तक 17 साल 3 महीने पूरे हो चुके हैं. यदि सीएमडी को इतना भी ज्ञान नहीं है कि उसके उपक्रम के गठन को कितना समय हो चुका है, तब उसकी सोच और जानकारी पर सिर्फ तरस ही आ सकता है.

आईआरसीटीसी के एक पूर्व रीजनल डायरेक्टर और एक पूर्व जीजीएम का कहना है कि एक ही जगह 15-16 साल तक किसी कर्मचारी या अधिकारी को पदस्थ रखा जाना न सिर्फ नियमों के विरुद्ध है, बल्कि यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना भी है. उन्होंने भी कहा कि अनिल गुप्ता को फौरन अन्यत्र शिफ्ट किया जाना चाहिए और इस बात की गहराई से जांच होनी चाहिए कि इतने सालों तक किस-किसने उसे एक ही जगह बनाए रखने में मदद की?

**# सुरक्षा कारणों से शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी गई है.**

# मुखिया रहित हुआ पूर्वोत्तर रेलवे का कमर्शियल विभाग

गोरखपुर ब्यूरो

- सीसीएम ए.पी.सिंह एमडी बनकर गए इरिटेम, लखनऊ, अब एक भी एचओडी नहीं बचा
- सीसीएम/पीएस, सीसीएम/पीएम, सीसीएम/एफएम की पोस्टें लगभग दो साल से हैं रिक्त
- पूर्वोत्तर रेलवे का पूरा कमर्शियल विभाग हुआ अब डिप्टी स्तर के प्रमोटी अधिकारियों के हवाले
- लगभग एक साल से खाली पड़ी है उत्तर पश्चिम रेलवे के सीओएम की पोस्ट, एमटी साधे मौन

पूर्वोत्तर रेलवे का पूरा कमर्शियल विभाग मुखिया रहित हो गया है. विभाग की सीसीएम/पीएस, सीसीएम/पीएम, सीसीएम/एफएम की पोस्टें लगभग दो साल से रिक्त पड़ी हुई हैं और अब इसके मुखिया सीसीएम ए. पी. सिंह का भी ट्रांसफर पूर्वोत्तर रेलवे के सीसीएम की पोस्ट के एलीमेंट के साथ ट्रैफिक अधिकारियों के प्रशिक्षण संस्थान 'इरिटेम' लखनऊ कर दिया गया है. श्री सिंह को 13 दिसंबर को इरिटेम के लिए रिलीव भी कर दिया है. अब पूर्वोत्तर रेलवे का पूरा कमर्शियल विभाग डिप्टी स्तर के सभी प्रमोटी अधिकारियों के हवाले है. ए. पी. के शब्दों में यह सब प्रमोटी अधिकारी पूरा विभाग संभालने में सक्षम हैं. ऐसे में सवाल यह उठता है कि फिर क्यों न पूर्वोत्तर रेलवे की सीसीएम सहित सीसीएम/पीएस, सीसीएम/पीएम और सीसीएम/एफएम की पोस्टों को ही समाप्त कर दिया जाए?

उधर उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के मुख्य परिचालन प्रबंधक (सीओएम) और मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (सीसीएम) की पोस्टें लगभग एक साल से खाली पड़ी हुई हैं. जबकि दक्षिण पश्चिम रेलवे के सीसीएम की पोस्ट को भी खाली पड़े लगभग इतना ही समय हो चुका है. आईआरटीएस का एचएजी पैनल पारित हुए भी लगभग पंद्रह दिन का समय बीत चुका है, परंतु अब तक उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण पदों पर पोस्टिंग करने के लिए रेलवे बोर्ड को समय नहीं मिला है. इसके परिणामस्वरूप माल यातायात और वाणिज्य की आय में लगातार गिरावट आती जा रही है. रेलवे बोर्ड को इस सब की कोई चिंता नहीं है, जबकि रेलमंत्री को उद्घाटनों से न तो फुर्सत है और न ही उन्हें इस बात की कोई चिंता है कि उनके पीछे रेलवे बोर्ड के अधिकारी क्या-क्या गुल खिला रहे हैं.

इसके अलावा एक सीसीएम को कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और कुछ निहितस्वार्थी लोगों के कहने या शिकायत करने पर अन्यत्र ट्रांसफर किए जाने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं, जबकि उसके रिटायरमेंट में अब कुछ ही महीने शेष बचे हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार जहां कुछ सीसीएम और सीओएम अपनी मनमानी करते हुए अवैध रूप से अकूत धन कमा रहे हैं, वहीं रेलवे बोर्ड का उन पर कोई वश नहीं चल रहा है. जबकि कुछ सीओएम और सीसीएम को अनावश्यक रूप से इधर-उधर करने की कुटिल चालें चली जा रही हैं. इस तरह पूरी भारतीय रेल के परिचालन और वाणिज्य विभाग दिशाहीन होकर काम कर रहे हैं. ऐसे में बहुत जल्दी ही कुछ सीसीएम और सीओएम की कलई खुलकर सामने आएगी.

## उ.म.रे. द्वारा कैशलेस ट्रांजेक्शन की शुरुआत

**इलाहाबाद :** कैशलेस ट्रांजेक्शन को और सुदृढ बनाने के लिए भारतीय रेल के विभिन्न स्थानों एवं स्टेशनों पर पीओएस मशीन (स्वाइप मशीन) लगाने का निर्णय लिया गया है. इस क्रम में प्रथम चरण में उत्तर मध्य रेलवे परिक्षेत्र में आने वाले इलाहाबाद, आगरा एवं झांसी मंडल के सभी ए1, ए एवं बी कैटेगरी के स्टेशनों पर आरक्षित टिकट हेतु 65 पीओएस मशीनें लगाई जा रही हैं. इन मशीनों के माध्यम से यात्री क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम आरक्षित टिकट प्राप्त कर सकते हैं. इस योजना के तहत इलाहाबाद में 4, कानपुर में 4, अनवरगंज में 1, इटावा में 1, शिकोहाबाद में 1 एवं राजा की मंडी में 2 मशीनें लगा दी गई हैं. इलाहाबाद जंक्शन पर 13 दिसंबर 2016 से इसके माध्यम से टिकट जारी करना भी शुरू कर दिया गया है. निकट भविष्य में इसके दूसरे चरण में उत्तर मध्य रेलवे के सभी यात्री आरक्षण केंद्रों, अनारक्षित टिकट केंद्रों एवं पार्सल/माल बुकिंग/यातायात केंद्रों, जहां भी नकद भुगतान होता है, पर लगाया जाएगा.

# आरसीटी में सेलेक्शन की इतनी जल्दी क्यों है?

सुरेश त्रिपाठी

जहां एक तरफ नोटबंदी के चलते पूरी सरकार अपने में ध्वस्त (व्यस्त) है, वहीं दूसरी तरफ रेलमंत्री की अनभिज्ञता के चलते और रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में स्टोरकीपर सीआरबी की पुनर्नियुक्ति से हताश-निराश सभी बोर्ड मेंबर अपनी अनमनस्कता के कारण अपने निर्धारित कार्यों को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं. 30 सितंबर, 2016 को 'रेलवे समाचार' द्वारा 'आरसीटी का पूर्व नोटिफिकेशन रद्द करके नया नोटिफिकेशन निकालने का दबाव' शीर्षक से प्रकाशित खबर में जो संभावना व्यक्त की गई थी, आखिर सही साबित हुई और आरसीटी का पूर्व नोटिफिकेशन रद्द करके नया नोटिफिकेशन निकाल दिया गया. खबर यह है कि इस दूसरे नोटिफिकेशन में उम्मीदवारों को आवेदन का पर्याप्त समय नहीं दिया गया और अब आरसीटी में सेलेक्शन के लिए 21-22 दिसंबर को इंटरव्यू लिए जाने वाले हैं, मगर इसके लिए भी किसी उम्मीदवार को इसकी लिखित सूचना अब तक नहीं दी गई है.

इसके अलावा उम्मीदवार अधिकारियों का कहना है कि इंटरव्यू के लिए उन्हें पंद्रह दिनों का भी समय नहीं दिया गया है. इससे लगभग सभी उम्मीदवार अधिकारी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें अपने दैनंदिन कामकाज के साथ इस इंटरव्यू की तैयारी करने का समय नहीं मिल रहा है. रेलवे बोर्ड के हमारे विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार आरसीटी सेलेक्शन में जूनियर्स को दरकिनार करने और अपने चहेते सीनियर्स का फेवर करने के लिए दुबारा नोटिफिकेशन निकाला गया है. सूत्रों का कहना है कि यह दूसरा नोटिफिकेशन फाइनेंस कमिश्नर (एफसी) और कुछ अन्य सीनियर अधिकारियों को एडजस्ट करने के लिए निकाला गया, क्योंकि उन्होंने बोर्ड में ही उच्च पदों पर अपने प्रमोशन के चक्कर में पहले वाले नोटिफिकेशन में आवेदन नहीं किया था.

- किसको फेवर करने हेतु की जा रही है यह जल्दबाजी?
- आरसीटी का पहला नोटिफिकेशन क्यों और किस आधार पर रद्द किया गया?
- आरसीटी सेलेक्शन की पूरी प्रक्रिया को रोक कर पूरे मामले की जांच होनी चाहिए

अधिकारियों का यह भी कहना है कि आरसीटी में पिछले साल के 16 पदों को गत अक्टूबर में भरने के तुरंत बाद बाकी पदों की वैकेंसी निकाली जा सकती थी. इसके बाद चालू वर्ष के बाकी पदों के लिए नोटिफिकेशन किया जा सकता था. उनका कहना है कि यह जल्दबाजी और पुराना नोटिफिकेशन रद्द करने की कार्रवाई आरसीटी में एफसी एवं कुछ अन्य सीनियर्स को फेवर करने हेतु की जा रही है, उन्हीं के लिए पिछला नोटिफिकेशन रद्द किया गया है. उन्होंने कहा कि पिछला नोटिफिकेशन रद्द किए जाने के पीछे एक कारण यह भी रहा है कि यदि उसे रद्द नहीं किया जाता, तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बंगलौर आदि बड़े शहरों की महत्वपूर्ण पोस्टें पहले ही भर जातीं, तब न तो सीनियर्स को फेवर किया जा सकता था और न ही उन्हें उनकी च्वाइस पोस्टिंग मिल पाती.

सूत्रों का कहना है कि इसीलिए पहला नोटिफिकेशन को रद्द किया गया और अब बिना किसी को कॉल लेटर भेजे और इंटरव्यू के लिए बिना 15 दिन का पर्याप्त समय दिए यह सेलेक्शन एकदम जल्दबाजी में किए जा रहे हैं. सूत्रों ने यह भी बताया कि गत मंगलवार को खुद मेंबर ट्रैफिक सुप्रीम कोर्ट जाकर उसके एक जज से इसके लिए समय लेकर आए हैं, क्योंकि 24 दिसंबर से अदालतों की शीतकालीन छुट्टियां शुरू हो रही हैं. जाहिर है कि एफसी सहित कुछ सीनियर्स को फेवर करने की किस कदर जल्दी है. उल्लेखनीय है कि आरसीटी के इंटरव्यू बोर्ड में सुप्रीम कोर्ट का एक जज, मेंबर ट्रैफिक, आरसीटी का चेयरमैन और एफसी होते हैं, इस बार चूंकि एफसी खुद एक उम्मीदवार हैं, इसलिए उनकी जगह मेंबर मैकेनिकल अथवा मेंबर स्टाफ में से कोई एक सदस्य होगा.

प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले के 16 पदों सहित इस साल के 3 पद और जोड़कर वर्तमान में आरसीटी में कुल 19 पदों के लिए सेलेक्शन होना है, जिनका साक्षात्कार 21-22 दिसंबर को जल्दबाजी में किया जा रहा है. कई अधिकारियों का कहना है कि अब च्वाइस पोस्टिंग तो सीनियर्स को देकर उनका फेवर किया जाएगा, जबकि जूनियर्स को फालतू पदों पर जाना पड़ेगा अथवा उन्हें वहां जाने से मना करके रेलवे से ही रिटायर होना पड़ेगा. उनका यह भी कहना है कि पहले वाला नोटिफिकेशन क्यों रद्द किया गया, किस आधार पर रद्द किया गया, इसका कोई उचित कारण बताने को रेलवे बोर्ड तैयार नहीं है. उन्होंने कहा कि अब आरसीटी सेलेक्शन में पहले की वैकेंसी के लिए पहले आवेदन किए हुए अधिकारियों का इंटरव्यू अलग से करके पहले उन्हें पोस्टिंग दी जानी चाहिए और बाद की वैकेंसी के लिए बाद में आवेदन करने वाले अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाना चाहिए अथवा इस पूरी प्रक्रिया को रोक कर इस पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए.

# दिल्ली के स्टेशनों पर बदले गए 50 करोड़ के पुराने नोट, कोई जांच नहीं !

**मुंबई :** सीबीआई ने मुंबई मंडल, मध्य रेलवे के एक सहायक वाणिज्य प्रबंधक (एसीएम) को तीन अलग-अलग स्टेशनों से कुल 8.22 लाख रुपए बदलने के आरोप में पकड़ा. इसके बाद उक्त अधिकारी को मुंबई मंडल से ट्रांसफर करके मुख्यालय, सीएसटी में बैठा दिया गया है. उल्लेखनीय है कि नोटबंदी का फैसला लागू होने के बाद से देश भर में सीबीआई सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा छापेमारी का दौर जारी है. कालाधन सफेद करने के आरोप में आरबीआई सहित कई बैंकों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के पकड़े जाने के बाद अब रेलवे पर भी सीबीआई ने अपनी पैनी दृष्टि डाली है.

- दिल्ली मंडल ने पार्सल बुकिंग में भी पुराने नोट लिए जाने की अनुमति दी
- मुंबई में अधिकारी ने बदलवाए 8.22 लाख रु. सीबीआई ने पकड़ा, ट्रांसफर

प्राप्त जानकारी के अनुसार सीबीआई ने मध्य रेलवे, मुंबई मंडल में कार्यरत रेलवे के असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर को नोटों की अदला-बदली के आरोप में पकड़ा है. एसीएम के. एल. भोयर नामक इस अधिकारी पर आरोप है कि उसने 8.22 लाख रुपए के पुराने नोटों को 2000 रुपए के नए नोटों से बदला है. सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि आरोपी एसीएम के. एल. भोयर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. भोयर के खिलाफ आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है.

बताते हैं कि एसीएम भोयर ने 8.22 लाख के पुराने नोटों को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठाणे और कल्याण स्टेशन के बुकिंग काउंटर पर बदला है. भोयर ने तीनों टिकट बुकिंग कार्यालयों से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों के बदले में 2000 रुपए के नए नोट और 100 रुपए के नोट भी लिए थे. केस दर्ज करने के बाद सीबीआई ने भोयर के कार्यालय और निजी आवास की भी तलाशी ली है. सीबीआई द्वारा मामला दर्ज होने के बाद भोयर को मंडल से ट्रांसफर करके मुख्यालय में भेज दिया गया है. अन्य कार्यवाही सीबीआई द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार की जाएगी.

नोटबंदी के बाद भले ही के. एल. भोयर पकड़ में आने वाले पहले रेल अधिकारी हों, मगर यह सही है कि 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के बाद बड़े पैमाने पर रेल अधिकारियों ने 500 एवं 1000 के पुराने नोटों अथवा अपनी अवैध कमाई को रेलवे स्टेशनों के बुकिंग काउंटरों से बदलवाया है. 9 नवंबर को ही यह खबर जबलपुर से आई थी कि 8-9 नवंबर की रात को नोटबंदी की घोषणा के तुरंत बाद जबलपुर मंडल, पश्चिम मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारी ने करीब 2.50 लाख के पुराने नोटों को जबलपुर स्टेशन के टिकट बुकिंग काउंटर से बदल लिया. इसी प्रकार दिल्ली में नई दिल्ली स्टेशन से उसी रात 50 लाख रुपए के पुराने नोटों को उत्तर रेलवे के बड़े वाणिज्य अधिकारी द्वारा बदलवाने की भी खबर आई.

इसके अलावा नई दिल्ली एवं पुरानी दिल्ली स्टेशनों सहित आसपास के अन्य सभी रेलवे स्टेशनों से 8 नवंबर के बाद के अगले 8-10 दिनों के दरम्यान करीब 50 करोड़ रुपए के पुराने नोट उत्तर रेलवे मुख्यालय सहित दिल्ली मंडल और रेलवे बोर्ड के तमाम अधिकारियों ने बदलवा लिए, जिसकी चर्चा आज भी है. ज्ञातव्य है कि दिल्ली के सभी स्टेशनों को मिलाकर प्रतिदिन करीब 6-7 करोड़ रुपए जमा होते हैं. इसके साथ ही दिल्ली मंडल द्वारा पार्सल बुकिंग में भी पुराने नोट लिए जाने की अनुमति दे दी गई, जबकि सरकार ने स्पष्ट घोषित किया था कि पुराने नोटों से सिर्फ रेलवे टिकट की ही बुकिंग कराई जा सकती है. जानकारों का मानना है कि यदि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे सिर्फ बड़े शहरों के ही रेलवे स्टेशनों के बुकिंग काउंटरों के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए जाएं, तो इस कालिख पर सफेदी पोतने वाले तमाम रेल अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा सकता है.

# 'एकाउंटिंग रिफॉर्म्स इन इंडियन रेलवेज– ए स्ट्रेटेजिक मिशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ'

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार, 20 दिसंबर को 'एकाउंटिंग रिफॉर्म्स इन इंडियन रेलवेज - ए स्ट्रेटेजिक मिशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ' विषय पर राष्ट्रीय कांफ्रेंस का आयोजन किया गया. कांफ्रेंस का उदघाटन रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने किया. इस अवसर पर केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली सहित फाइनेंस कमिश्नर/रेलवेज शहजाद शाह, एडवाइजर एकाउंट्स नरेश सालेचा और राकेश भारती मित्तल सहित अन्य गणमान्य लोग मंच पर उपस्थित थे. इसके अलावा रेलवे बोर्ड के मेंबर इंजीनियरिंग ए. के. मित्तल, मेंबर ट्रैक्शन ए. के. कपूर, मेंबर रोलिंग स्टॉक रवीन्द्र गुप्ता, मेंबर ट्रैफिक मोहम्मद जमशेद सहित रेलवे बोर्ड के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे.

# समस्या पैदा करना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के समान है...

- आरपीएसएफ को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है
- बचकानी बातें करना आईपीएस के लोगों को शोभा नहीं देता है
- आरपीएसएफ का गैर-कानूनी ढ़ंग से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे खत्म किया जाना चाहिए
- बोर्ड के अधिकारी सीबीआई और आईपीएस अधिकारियों से लड़ नहीं सकते हैं, उनसे डरते हैं
- सीबीआई से तो सरकार भी डरती है, तब रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को ही क्यों दोष दिया जाए
- रिस्ट्रक्चरिंग का मामला वित्त मंत्रालय को रेफर किए जाने का अनावश्यक कदम उठाया गया
- एसोसिएशन विरोधी गतिविधियों के लिए दो जोनल पदाधिकारी प्राथमिक सदस्यता से निलंबित

**पेज 1 का शेष...** पदाधिकारियों ने घोर निंदा की. बैठक में रिस्ट्रक्चरिंग सहित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए गए और रेल प्रशासन से आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई. इस मौके पर दो जोनल पदाधिकारियों को एसोसिएशन विरोधी गतिविधियों के लिए 6-6 साल के लिए एसोसिएशन की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया, जो कि श्रमिक सगठनों के लिए एक बड़ा सबकपूर्ण उदाहरण हो सकता है.

बैठक का औपचारिक उदघाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष एस. आर. रेड्डी, राष्ट्रीय महामंत्री यू. एस. झा एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बी. एल. बिश्नोई ने बारी-बारी से दीप प्रज्वलित करके किया. उनके साथ मेजबान उत्तर मध्य रेलवे के महामंत्री ओमप्रकाश और उनके सभी सहयोगी भी थे. तत्पश्चात बैठक की औपचारिक शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम राष्ट्रीय महामंत्री यू. एस. झा ने पूरी भारतीय रेल पर वर्तमान वातावरण का उल्लेख करते हुए विधि-सम्मत वक्तव्य दिया तथा रेलवे बोर्ड एवं अदालत तक चल रही तमाम गतिविधियों से उपस्थित एसोसिएशन के पदाधिकारियों को अवगत कराया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2003-04 में ही बाजपेई सरकार के समय रेलवे बोर्ड स्तर पर यह निर्णय हो चुका था कि एसोसिएशन के साथ पीएनएम मीटिंग की जाएगी और यह भी तय हो चुका था कि आरपीएसएफ का आरपीएफ में विलय कर दिया जाएगा. इसके साथ ही रिस्ट्रक्चरिंग का भी समय निर्धारण हुआ था. परंतु इसे वित्त मंत्रालय को भेजने का अनावश्यक कदम उठाया गया. इन्हें कोई बताने वाला नहीं है, बताना तो डीजी को था, मगर डीजी ने तो स्वयं रुकावट डालने के लिए इसे वित्त मंत्रालय को रेफर किया था. वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय को आरपीएफ की रिस्ट्रक्चरिंग के मामले को भेजे जाने का कोई औचित्य नहीं था. उन्होंने कहा कि जब वर्ष 2004 में ही यह निर्णय हो चुका था कि तय समय पर रिस्ट्रक्चरिंग होगी, तब इसे क्यों भेजा गया?

उन्होंने बताया कि आरपीएफ में बाहर से आने वाले अधिकारी पहले गृह मंत्रालय में अपनी सेटिंग करके और अपने प्रवक्ता बनाकर अपनी ऊल-जलूल बातों को प्रचारित करवाते हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व डीजी ने प्रश्न उठवाया था कि सीआरपीएफ और बीएसएफ की तुलना में आरपीएफ में अधिकारियों की संख्या ज्यादा है. इस पर जब हमसे लोगों ने पूछा तो हमने यही कहा कि सीआरपीएफ और बीएसएफ चौकीदार हैं. उन्होंने कहा कि ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं, क्योंकि इन्हें जानकारी नहीं है, और यदि है भी, तो ये लोग उसे साइडलाइन करके अपनी बचकानी हरकतें करने में लगे रहते हैं. उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय से यह लिखकर पूछा गया कि आरपीएफ और आरपीएसएफ में अधिकारियों की संख्या ज्यादा क्यों है? इस पर जब मैंने कहा कि डीजी/आरपीएफ 'बुढ़बक' (बेवकूफ) है, आरपीएफ को जांच और इन्वेस्टीगेशन का अधिकार मिला हुआ है, केवल प्रोटेक्शन और चौकीदारी होती, तो अधिकारी कम होते. इन्वेस्टीगेशन की टीम ज्यादा बड़ी होती है. डीजी पुलिस से हैं, तो उन्हें यह बात पता होनी चाहिए कि पुलिस में अधिकारी क्यों ज्यादा हैं? उन्होंने कहा कि राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ में वही अंतर होगा, जो आरपीएफ और उनमें है. तब एकदम चुप रह गए थे.

श्री झा ने कहा कि आईपीएस के लोग यही मानते हैं कि पूरी दुनिया मूर्ख है, वह जो कहेंगे, वही सत्य होगा, परंतु ऐसा वास्तव में नहीं है. उन्होंने कहा कि अपने लोग भी यही मानते हैं कि वह जो कहेंगे वही सही होगा. इसीलिए वह लोग इन्हें मूर्ख समझते हैं. जब हमने इसका जवाब दे दिया, तो सब ठंडे पड़ गए. इसके बाद उन्होंने आरपीएसएफ का मामला उठाया. इस पर भी डीजी की मुर्खता ही साबित हुई, क्योंकि आरपीएसएफ से बदली होकर उसके जवान आरपीएफ में आते हैं, करीब एक-डेढ़ साल पहले लगभग छह-सात हजार जवान वहां से आरपीएफ में बदली होकर आए हैं. उन्होंने कहा कि आरपीएफ से भी आरपीएसएफ में ट्रांसफर होकर जाते हैं. ऐसे में जब यह इंटर-ट्रांस्फरेबल हैं, तो उन्हें भी इन्वेस्टीगेशन का पॉवर होता है. आरपीएसएफ के अधिकारियों को भी इन्वेस्टीगेशन का प्रशिक्षण होता है. यदि ऐसा नहीं होता, तो वे इधर से उधर और उधर से इधर बदली होकर क्यों आते? उन्होंने कहा कि एक ही प्रशिक्षण संस्थान में सबका प्रशिक्षण होता है. तब ऐसी बचकानी बातें करना आईपीएस के लोगों को शोभा नहीं देता है.

उन्होंने कहा कि आज इस पर भी एक निर्णय लिया जाए और एक प्रस्ताव पारित किया जाए कि पूरी आरपीएसएफ को अधिकारियों ने गैर-इस्तेमाल के लिए बना रखा है, जबकि उसका कोई उचित उपयोग नहीं पा रहा है. उन्होंने कहा कि आरपीएसएफ को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है. उनका स्पष्ट कहना था कि जब भी रेलवे के या किसी बाहरी अधिकारी को 'ओब्लाइज' करना होता है, उसके घर पर और उसके एवं उसके घर-परिवार वालों के आगे-पीछे 10-10 तमंचाधारी आरपीएसएफ के जवानों को बेगार भुगतने के लिए भेज दिया जाता है. इस तरह से वर्दीधारी जवानों सहित वर्दी का भी अपमान किया जाता है. उन्होंने कहा कि इस देश का चरित्र ही ख़राब हो गया है, जब भी कोई इस प्रकार की मुफ्तखोरी करता है, तो उसकी बड़ी वाहवाही होती है. क्या यह सब डीजी के बाप की बपौती है, और यदि ऐसा है, और बहुत सा पैसा चोरी-चमारी करके कमा लिया है, तो अपने खर्च पर लोगों को 10-10 जवानों की सुरक्षा उपलब्ध कराए. आरपीएसएफ को गैर-कानूनी ढ़ंग से क्यों इस्तेमाल किया जाता है? उन्होंने कहा कि इन लोगों ने आरपीएसएफ को इसीलिए बनाए रखा है कि उन्हें किसी न किसी अधिकारी को खुश करते रहना है. डीजी के घर पर 15-16 जवानों की ड्यूटी लगाए जाने पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया.

उन्होंने आगे कहा कि कभी युद्ध के समय आरपीएसएफ की जरुरत महसूस हुई होगी, मगर वर्तमान परिस्थितियों में आरपीएसएफ को बनाए रखने का कोई भी औचित्य नहीं रह गया है. इस बारे में आज यहां एक मजबूत संकल्प लेते हुए प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए कि आरपीएसएफ को तत्काल प्रभाव से आरपीएफ में मर्ज किया जाना चाहिए. यह मांग पहले भी की गई है और लगातार की जा रही है. इसके रिकार्ड्स रेलवे बोर्ड सहित एसोसिएशन के पास भी मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 में रेलवे बोर्ड ने पूर्वोत्तर सीमांत और जम्मू एवं कश्मीर की दो बटालियनों को छोड़कर बाकी सभी बटालियनों का आरपीएफ में विलय किए जाने का आदेश जारी हुआ था. यह आरपीएफ एसोसिएशन की मांग पर ही संभव हो पाया था. परंतु उनका यह भी कहना था कि बोर्ड के अधिकारियों की परेशानी यह है कि सीबीआई और आईपीएस अधिकारियों से वह नहीं लड़ सकते हैं, उनसे डरते हैं. उनका कहना था कि ऐसा नहीं कि बोर्ड के अधिकारी चोर या भ्रष्ट हैं, मगर उनका डर सिर्फ इस बात से रहता है कि ये लोग जबरदस्ती फर्जी मामलों में भी फांस देते हैं. उन्होंने कहा कि बोर्ड के अधिकारी इनसे इसलिए घबराते हैं, क्योंकि यदि झूठे मामले में भी फांस देगा, तो पांच-दस साल तक उनकी पदोन्नति तो रुक ही जाती है, बल्कि इससे उनकी सामाजिक छवि भी ख़राब होती है. यही नहीं, सीबीआई के डर से तो सरकार भी चुप हो जाती है. तब रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को ही क्यों दोष दिया जाए.

श्री झा ने यह भी कहा कि हम लोगों को सरकार को भी थोड़ा समझाने की जरुरत है, क्योंकि यदि सरकार ही सीबीआई से डरेगी, तो पूरा देश उससे डरेगा और इसका प्रभाव देश की समस्त गतिविधियों पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि ऐसा भी नहीं है कि लोग इन सब बातों को समझते नहीं हैं, मगर जो लोग ऐसा मानते हैं, वह मूर्ख हैं. उनका कहना था कि लोग समझकर भी चुप इसलिए हैं, क्योंकि वह शरीफ हैं, नंगे के साथ कोई नंगा नहीं होना चाहेगा, परंतु यदि ऐसा कोई समय आ गया, तो लोग उनके साथ नंगई से पेश आने से भी पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने कहा कि इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण ही यह देश बारह सौ साल तक गुलाम रहा है. उनका कहना था कि हमारे लोग आपस में लड़ने में बहुत माहिर हैं, मगर वहीं जब कोई दूसरा आ जाता है, तो पैंट में पेशाब कर देते हैं. यही वजह रही है कि मुट्ठी भर लोगों ने हम करोड़ों लोगों पर बारह सौ साल तक राज किया. उन्होंने कहा कि हमें इस प्रवृत्ति को छोड़ना होगा और इस मुद्दे पर पूरे देश में खुली बहस होनी चाहिए. उन्होंने सरकार से भी आग्रह किया कि वह भी इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे कि यह देश बारह सौ साल तक गुलाम क्यों रहा?

उन्होंने इस संदर्भ में आगे कहा कि पूरे देश में रोजाना करीब तीन करोड़ लोग पूरी भारतीय रेल में असुरक्षित यात्रा करते हैं. उनके अंदर यह पुख्ता धारणा बन गई कि चलती ट्रेन में कहीं भी चोरी-डकैती अथवा छेड़छाड़, हत्या-बलात्कार हो जाए, उनकी शिकायत का कोई हल निकलने वाला नहीं है. इसलिए वह चुपचाप बिना शिकायत दर्ज कराए चले जाते हैं. इसका कारण यह है कि ट्रेन/रेल अनेक राज्यों से होकर गुजरती है, एक राज्य की पुलिस को उसके राज्य के अंदर ही अधिकार प्राप्त है. अपराध एक राज्य में होता है, मगर जिस-जिस राज्य से होकर ट्रेन गुजरती है, उन-उन राज्यों की पुलिस कहती है कि उनके यहाँ कोई अपराध नहीं हुआ. यात्री चलता है एक राज्य से, उसके साथ अपराध होता है किसी दूसरे राज्य में, उसे अपराध की जानकारी होती है किसी तीसरे राज्य में और जब वह उसकी शिकायत देने की तैयारी करता है तब तक चौथा राज्य आ जाता है. ऐसे में चार-पांच राज्यों के गुजर जाने के बाद एफआईआर दर्ज होती है. वह एफआईआर 'जीरो' में दर्ज होकर पूरे देश में घूमती रहती है. उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता है और 'केस बंद' की रिपोर्ट लगाकर फाइल दाखिल दफ्तर कर दी जाती है.

श्री झा ने कहा कि इस तरह की भीषण दुर्व्यवस्था विश्व के किसी भी देश में नहीं है, जैसी इस देश में रेलवे के साथ चल रही है. उनका कहना था कि इस मामले पर सरकार को समझना और समझाना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि हम यह नहीं कहते हैं कि आरपीएफ को ही सर्वाधिकार संपन्न बनाया जाए, इसकी जगह कोई दूसरी एजेंसी भी हो सकती है. चूंकि आरपीएफ पर रेलवे की समस्त संपत्ति और यात्री सहित उसके माल-असबाब की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो रेलवे उन्हें सुरक्षा देने के लिए उत्तरदायी है. ऐसा न हो पाने अथवा अपराध होने या प्रबंधकीय लापरवाही के कारण हुई क्षति की भरपाई करने का उत्तरदायित्व रेलवे का है. इसीलिए आरपीएफ को और मजबूत एवं अधिकार संपन्न बनाया जाना आवश्यक है. आरपीएफ के रहते हुए भी यात्रियों का माल-असबाब चोरी होता है, रेलवे संपत्ति की चोरी होती है. इसकी इन्वेस्टीगेशन का अधिकार आरपीएफ को नहीं है. तथापि आरपीएफ कर्मियों को इसके लिए चार्ज शीट दी जाती है. निलंबित किया जाता है, वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जाती है, वेतन की भी कटौती कर दी जाती है, और यहां तक कि बर्खास्त भी किया जाता है. उनका कहना था कि जब आरपीएफ को उपरोक्त अपराधों की रोकथाम का अधिकार ही नहीं है, तो इस प्रकार की विभागीय कार्यवाहियों से कुछ हासिल नहीं होना है, बल्कि इससे और ज्यादा नुकसान हो रहा है.

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 1947 से ही यह मांग की जाती रही है कि रेलवे की अपनी फोर्स को पॉवर दिया जाना चाहिए. मगर तब से लेकर अब तक सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी है. इस दरम्यान कई समितियों ने इस बारे में अपनी रिपोर्ट भी दी है. ऐसा भी नहीं है कि सरकार इस तरह से होने वाले नुकसान से अनभिज्ञ है, उसे सब कुछ पता है, क्योंकि नुकसान की भरपाई तो सरकार को ही करना पड़ रहा है, मगर सरकार भी आईपीएस से डरती है. सभी पार्टियों के नेता सीबीआई से डरते हैं. ऐसा क्यों है, इसकी गहराई में ज्यादा जाने की जरुरत नहीं है, क्योंकि इस बारे में सब जानते हैं कि ऐसा क्यों है? इसलिए आज यह प्रस्ताव पारित किया जाए कि आरपीएफ को संपूर्ण अधिकार संपन्न बनाया जाए और आरपीएसएफ को आरपीएफ में संपूर्ण विलय किया जाए. श्री झा के उक्त दोनों प्रस्ताव सभा ने ध्वनि मत से पारित कर दिए.

उन्होंने यह भी कहा कि पीएनएम से आरपीएफ प्रशासन इसलिए भाग रहा है, क्योंकि पीएनएम से यदि सभी समस्याएं हल हो जाएंगी, तो फिर अधिकारियों के पास कोई नहीं जाएगा. उन्हें मुफ्त की लगी हुई लत की पूर्ति कैसे होगी. रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी, इसलिए अधिकारी वर्ग नहीं चाहता है कि आरपीएफ एसोसिएशन को दिए गए अधिकारों का **शेष पेज 7 पर...**

# उ. प्र. में यात्री सुविधा के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जा रहे हैं..

**पेज 1 का शेष...** के 11 स्टेशनों पर पाइप्ड जल आपूर्ति, बिल्हौर, बर्राजपुर एवं कायमगंज स्टेशनों पर पैदल उपरिगामी पुलों का लोकार्पण एवं इज्जतनगर स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार का शिलान्यास फलक का अनावरण किया. समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, संतोष कुमार गंगवार ने की.

समारोह को संबोधित करते हुए रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि बरेली सिटी स्टेशन के द्वितीय प्रवेष द्वार एवं उन्नत यात्री सुविधाओं, इज्जतनगर मंडल के 11 स्टेशनों पर पाइप्ड जल आपूर्ति और बिल्हौर, बर्राजपुर एवं कायमगंज स्टेशनों पर पैदल उपरिगामी पुलों के लोकार्पण एवं इज्जतनगर स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार का शिलान्यास किया जा रहा है. 28 नवंबर, 2015 को बरेली सिटी स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार एवं उन्नत यात्री सुविधाओं का शिलान्यास किया गया था और यह परियोजना निर्धारित समय में पूर्ण की गई है. इसके लिए मैं पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्र को हार्दिक बधाई देता हूं. उन्होंने कहा कि इज्जतनगर मंडल के 11 स्टेशनों पर 1.01 करोड़ रुपए की लागत से टैप वाटर सप्लाई उपलब्ध कराई जा रही है. बिल्हौर, बर्राजपुर एवं कायमगंज स्टेशनों पर पैदल उपरिगामी पुलों का निर्माण किया गया है. कुल 1.52 करोड़ रुपए की लागत से इज्जतनगर स्टेशन पर द्वितीय प्रवेश द्वार के निर्माण को मंजूरी दी गई है. इसका कार्य पूरा होने पर नगर के पूर्वी क्षेत्र के लोगों को सीधे प्लेटफार्म पर आने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी.

रेलमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में पूर्वोत्तर रेलवे पर यात्री सुविधा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं. इनमें 3 स्टेशनों पर 6 एस्केलेटरों का कार्य, 3 करोड़ रुपए की लागत से 110 स्टेशनों पर 193 ऑटोमेटेड टिकट वेंडिंग मशीनों का प्रावधान, 4 करोड़ रुपए की लागत से 2 स्टेशनों पर समेकित यात्री सुरक्षा प्रणाली का कार्य, 3.5 करोड़ रुपए की लागत से 35 वाटर वेंडिंग मशीनों की स्थापना के कार्य के अतिरिक्त 3300 यात्री बेंचेज, 595 यात्री छाजन एवं 62 नए शौचालयों के प्रावधान का कार्य सम्मिलित है.

श्री प्रभु ने कहा कि पिछले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश में 950 करोड़ रुपए की लागत से 213 किमी. रेल खंड का आमान परिवर्तन, 393 करोड़ रुपए की लागत से 74 किमी. रेल खंड का दोहरीकरण, 900 करोड़ रुपए की लागत से 987 किमी. रेल खंड का विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया है. इसी दौरान 182 उपरिगामी/अधोगामी पुलों का निर्माण किया गया. 41 नई गाड़ियों का संचालन प्रारम्भ किया गया, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे पर बलिया-आनन्द विहार टर्मिनस भृगु एक्सप्रेस, गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, गाजीपुर-कोलकाता शब्दभेदी एक्सप्रेस, गाजीपुर-आनन्द विहार टर्मिनस सुहेलदेव एक्सप्रेस, गोरखपुर-आनन्द विहार एक्सप्रेस, गोरखपुर-गोमतीनगर (वाया बढ़नी)

एक्सप्रेस, गोरखपुर-बादशाहनगर एक्सप्रेस, बस्ती-इलाहाबाद मनवर-संगम एक्सप्रेस, लखनऊ-आनन्द विहार टर्मिनस डबल डेकर गाड़ियाँ चलाई गई हैं. इसके अतिरिक्त मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया गया है. उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश में 36,689 करोड़ रुपए की लागत से आमान परिवर्तन, दोहरीकरण एवं नई रेल लाइनों के निर्माण के 37 कार्य स्वीकृत किए गए हैं. कुल 2,101 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे विद्युतीकरण के 12 कार्य स्वीकृत किए गए हैं. कुल 4,155 करोड़ रुपए की लागत से 307 उपरिगामी पुल/अधोगामी पुल/सब-वे के निर्माण को मंजूरी दी गई है.

उन्होंने कहा कि यात्री सुविधाओं में विस्तार हेतु 508 करोड़ रुपए की लागत से 451 कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है. पूर्वोत्तर एवं उत्तर मध्य रेलवे पर 58 एस्केलेटर एवं 53 लिफ्टों के कार्य को मंजूरी दी गई, जिनमें से 20 एस्केलेटर एवं एक लिफ्ट का कार्य पूरा हो चुका है. इस प्रकार पिछले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश में कुल 43,453 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं. रेलमंत्री ने कहा कि वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक औसत बजट आवंटन 1,109 करोड़ रुपए रहा है, जबकि वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक औसत बजट आवंटन 3,405 करोड़ रुपए है. इस प्रकार पिछले दो वर्षों में औसत बजट आवंटन उसके पिछले पाँच वर्षों के औसत के सापेक्ष तीन गुना किया गया है. वर्ष 2016-17 में कुल 4,923 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया.

इस प्रकार उत्तर प्रदेश में यात्री सुविधा के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है, जिससे कि यहां की जनता की यात्रा सुखद, सुरक्षित एवं आरामदेह हो सकेगी.

उन्होंने कहा कि हम अपने इन प्रयासों में पूरी तरह सफल हो रहे हैं. समारोह की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बरेली सिटी स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार का कार्य निर्धारित समय में पूरा किए जाने पर रेलमंत्री एवं पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्र की सराहना की. उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा यात्री सुविधा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है, जिसका लाभ सीधे यात्री जनता को मिल रहा है. वित्त राज्य मंत्री ने उत्तराखंड से बरेली होकर दक्षिण भारत के लिए ट्रेन चलाने की भी मांग की. उन्होंने कहा कि कई ट्रेनें लखनऊ या दिल्ली में 12 घंटे से अधिक रुकी रहती हैं. उन्हें बरेली या काठगोदाम तक बढ़ाया जाए. श्री गंगवार ने यह भी कहा कि श्यामतगंज स्थित माल गोदाम के पास जो रेलवे की काफी जमीन खाली पड़ी है, उसका यथोचित वाणिज्यिक उपयोग किया जाए. इसके अतिरिक्त उन्होंने रेल संबंधित जन आकांक्षाओं की ओर भी रेलमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया.

पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्र ने कहा कि बरेली सिटी स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार एवं उन्नत यात्री सुविधाओं हेतु वर्ष 2015-16 में 2 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृति प्रदान की गई थी. इसके अंतर्गत यात्रियों हेतु आगमन-प्रस्थान लाउन्ज, विशिष्ठ श्रेणी प्रतीक्षालय, महिला एवं पुरुष प्रतीक्षालय, टिकट घर, कैफेटेरिया, अधिकारी एवं कर्मचारी विश्रामालय सहित आकर्षक द्वितीय प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है. इन सुविधाओं के उपलब्ध हो जाने से शहर के पश्चिम की ओर से आने वाले यात्रियों को समपार पार किए बिना प्लेटफार्म संख्या 4, 2/3 से गाड़ी पकड़ने में सुविधा होगी. इसके अतिरिक्त भविष्य में इस स्टेशन पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाए जाने के बावजूद भीड़ को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी.

महाप्रबंधक श्री मिश्र ने कहा कि स्टेशनों पर यात्रियों को पीने के पानी हेतु पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा प्रभावी कदम उठाए गए हैं. इसके अंतर्गत इज्जतनगर मंडल के 11 स्टेशनों पर 1.01 करोड़ रुपए की लागत से जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार किया गया है. इस कार्य के पूरा हो जाने से इन 11 स्टेशनों पर यात्रियों को टैप वाटर सप्लाई उपलब्ध कराई जा रही है. महाप्रबंधक ने कहा कि इज्जतनगर मंडल के बिल्हौर, बर्राजपुर एवं कायमगंज स्टेशनों पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए पैदल उपरिगामी पुलों का निर्माण किया गया है. इन उपरिगामी पुलों के निर्माण पर 2.8 करोड़ रुपए की लागत आई है. महाप्रबंधक श्री मिश्र ने कहा कि इज्जतनगर स्टेशन पर 1.52 करोड़ रुपए की लागत से द्वितीय प्रवेश द्वार एवं यात्री सुविधाओं में सुधार एवं विस्तार का कार्य स्वीकृत किया गया है. इसके पूरा होने पर नगर के पूर्वी हिस्से के लोगों को ट्रैक पार किए बिना प्लेटफार्म पर आने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी.

मंडल रेल प्रबंधक, इज्जतनगर निखिल पांडेय ने अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया तथा समारोह का संचालन वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आर. सी. श्रीवास्तव ने किया.

# महाप्रबंधकों के रिक्त पदों पर एक साथ पोस्टिंग क्यों नहीं ?

**पेज 1 का शेष...** प्राप्त है. उनकी सभ्यता, सौम्यता, मिलनसारिता और ईमानदारी सुपरिचित है. इससे पहले उन्होंने भारतीय रेल के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, मगर बतौर महाप्रबंधक/म.रे. उनके सामने खासतौर पर मध्य रेलवे के उपनगरीय सेक्शन में आए दिन होने वाले रेल फ्रैक्चर, डिरेलमेंट और ओएचई फेल्यूर के कारण प्रभावित होने वाली उपनगरीय रेल सेवाओं को सुचारु रूप से चलाने और जनाक्रोश का शमन करने की एक बड़ी चुनौती है.

इस संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार महाप्रबंधक श्री शर्मा ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है. पता चला है कि कल्याण तक और कल्याण से आगे जिन अधिकारियों का कार्यक्षेत्र है, उन्हें श्री शर्मा ने कल्याण और इगतपुरी में रहने के लिए कहा है. इन अधिकारियों को उन्होंने कल्याण और इगतपुरी में उनके आवास भी आवंटित कर दिए हैं. इसके साथ ही यह भी हिदायत दी है कि वे हमेशा लाइन पर रहें. उनकी किसी प्रकार की लापरवाही और फेल्यूर को बर्दास्त नहीं किया जाएगा. श्री शर्मा ने मुंबई मंडल के सभी ब्रांच अफसरों को भी प्रतिदिन अपने-अपने कार्य का

**'रेलवे समाचार' की ट्वीट के बाद रे.बो. ने की सीएलडब्ल्यू में महाप्रबंधक की पोस्टिंग**

बारीकी से निरीक्षण करते रहने की सख्त हिदायत दी है. श्री शर्मा की जॉइनिंग के दो दिन बाद ही ब्लॉक ओवरसूट होने के कारण टिटवाला में हुए जनांदोलन के बाद श्री शर्मा ने प्रशासनिक सख्ती बरतने का निर्णय लिया है. बताते हैं कि वह खुद टिटवाला जाने के लिए तैयार हो गए थे, मगर डरपोक अधिकारियों ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया. श्री शर्मा ने अब औचक निरीक्षण करने का निर्णय किया है. इस निर्णय के अनुसार वह गत सप्ताह अचानक विक्रोली, ठाणे और कल्याण का निरीक्षण करने निकल पड़े, जिससे मुंबई मंडल के कई अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए थे.

बहरहाल, रेलवे बोर्ड द्वारा जिस दिन 30 नवंबर को श्री अग्रवाल और श्री शर्मा के बतौर महाप्रबंधक ऑर्डर जारी किए गए, उस दिन बतौर मेंबर रोलिंग स्टॉक रवीन्द्र गुप्ता के रेलवे बोर्ड में ज्वाइन कर लेने से दक्षिण मध्य रेलवे और सी. पी. तायल के रिटायरमेंट से चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (सीएलडब्ल्यू) के दो अन्य महाप्रबंधकों के पद भी रिक्त पड़े हुए थे. सवाल यह है कि मध्य रेलवे एवं दक्षिण पूर्व रेलवे के साथ ही दक्षिण मध्य रेलवे और सीएलडब्ल्यू के महाप्रबंधकों की पोस्टिंग के आदेश रेलवे बोर्ड द्वारा क्यों नहीं जारी किए गए? क्या कारण था कि सिर्फ नौ दिन के लिए एक महाभ्रष्ट महाप्रबंधक को सीएलडब्ल्यू का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया? यह अतिरिक्त चार्ज मेट्रो रेलवे के इलेक्ट्रिकल कैडर के ही महाप्रबंधक को भी तो सौंपा जा सकता था?

इस संदर्भ में जब 'रेलवे समाचार' ने उपरोक्त सवाल उठाते हुए 4-5 दिसंबर को रेलमंत्री, रेल मंत्रालय, प्रधानमंत्री और पीएमओ को ट्वीट किया, तब 9 दिसंबर को सीएलडब्ल्यू के लिए वी. पी. पाठक (आईआरएसएस - 1982 बैच) को महाप्रबंधक बनाए जाने का आदेश रेलवे बोर्ड ने जारी किया. यहां भी रेलवे बोर्ड ने दक्षिण मध्य रेलवे को छोड़ दिया. वहां महाप्रबंधक की पोस्टिंग आज लगभग पंद्रह दिन बीत जाने के बावजूद नहीं की गई है, जबकि जीएम पैनल रेलवे बोर्ड के पास पहले से ही तैयार पड़ा है. 'कलर-ब्लाइंड स्टोरकीपर' सीआरबी की कुटिल नीतियों के चलते वी. पी. पाठक स्टोर्स कैडर के वर्तमान में तीसरे महाप्रबंधक बन गए हैं. उल्लेखनीय है कि मई 2016 में एक आरटीआई के जरिए 'कलर ब्लाइंड' स्टोर्स अधिकारियों, जो की बतौर जीएम, डीआरएम, एडीआरएम कार्यरत हैं, के संबंध में मांगी गई जानकारी अब तक रेलवे बोर्ड ने नहीं दी है. इससे पहले ऐसे सभी अधिकारियों के संबंध में मांगी गई जानकारी देने से रेलवे बोर्ड ने साफ मना कर दिया था.

यदि ऐसा ही चलता रहा, तो दक्षिण मध्य रेलवे को भी रोशन लाल पवार (आईआरएसएस - 1982 बैच) के रूप में स्टोर्स कैडर का चौथा 'कलर-ब्लाइंड' महाप्रबंधक मिल सकता है. चूंकि 1 दिसंबर से दक्षिण मध्य रेलवे की जीएम पोस्ट रिक्त हुई है. जबकि जीएम के लिए श्री पवार के निर्धारित दो साल के कार्यकाल में एक महीना दस दिन कम हो गए हैं. ऐसे में रेलमंत्री की 'सेफ्टी' का क्या होगा, यह सिर्फ ईश्वर अथवा 'प्रभु' ही जानते हैं. वैसे भी प्रदूषण युक्त घने कोहरे ने रेल संचालन का बंटाधार किया हुआ है. लगभग सभी ट्रेनें 10-12 घंटों की देरी से चल रही हैं. प्रभु की तकनीक इसमें कोई काम नहीं आ रही है, जबकि कोहरे से निपटने के लिए अब तक रेलवे बोर्ड ने तमाम तरह के परीक्षणों में करोड़ों रुपए स्वाहा कर दिया है.

# पूर्वांचल की जनता की वर्षों पुरानी मांग...

**पेज 1 का शेष...** और गोरखपुर-नकहा जंगल दूसरी लाइन का शिलान्यास किया गया. समारोह में महापौर गोरखपुर डॉ. सत्या पांडेय, विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल, विधायक राजेश त्रिपाठी, सांसद हरीश द्विवेदी के प्रतिनिधि पंकज श्रीवास्तव तथा सांसद शरद त्रिपाठी के प्रतिनिधि सत्यप्रकाश पाठक सहित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्र, मंडल रेल प्रबंधक, लखनऊ आलोक सिंह, मुख्यालय एवं लखनऊ मंडल के वरिष्ठ रेल अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थिति थी.

बांद्रा स्टेशन पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने सांसद महंत योगी आदित्य नाथ, जगदम्बिका पाल, विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल, महापौर डॉ. सत्या पांडेय एवं पूर्वांचल की जनता को बधाई देते हुए कहा कि गोरखपुर क्षेत्र की बहुत पुरानी मांग पूरी हो रही है. पूर्वांचल की जनता रोजगार के लिए अपने परिवार से दूर जाकर रहती है, जिनके लिए यात्रायें कठिन होती हैं. सांसद जगदम्बिका पाल की मांग पर पूर्वांचल की जनता के लिए यह ट्रेन चलाई जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए जो योजना बनाई, उसमें रेल का महत्वपूर्ण का योगदान है. अतः रेल के विकास से देश का विकास होगा.

उन्होंने कहा कि गोरखपुर में एसी लोको शेड बनाने से, गोरखपुर-गोंडा रेल खंड का विद्युतीकरण होने से एवं डोमिनगढ़-गोरखपुर-गोरखपुर कैंट-कुसुम्ही तीसरी लाइन और गोरखपुर-नकहा जंगल की दूसरी लाइन बनने से स्थानीय जनता को काफी सुविधा होगी. रेलवे में सभी ट्रांजेक्शन कैशलेस किए जा रहे हैं. हम रेल के वेंडरों को डिजिटल प्लेटफार्म पर ला रहे हैं. रेलवे पर जो भी विकास होगा, उसका लाभ आम आदमी को मिलेगा.

**गोरखपुर-गोंडा रेलखंड के विद्युतीकरण का लोकार्पण, बांद्रा-गोरखपुर विशेष गाड़ी को हरी झंडी**

उन्होंने कहा कि हमने चार ट्रेनों की शुरूआत करने की बात कही थी, उसमें से एक ट्रेन 'हमसफर' की शुरूआत कर दी गई है, दूसरी तेजस ट्रेन जल्दी ही चलाई जाएगी, तीसरी अंत्योदय एक्सप्रेस को भी शीघ्र चलाया जाएगा तथा उदय ट्रेन रात को चलेगी और गंतव्य पर सुबह पहुंचाएगी. रेलमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन विशेष गाड़ी सं.05068 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस को रवाना किया. इस अवसर गोरखपुर-गोंडा रेल खंड के विद्युतीकरण का लोकार्पण, गोरखपुर में 100 लोको क्षमता वाला एसी लोको शेड एवं डोमिनगढ़-गोरखपुर-गोरखपुर कैंट-कुसुम्ही तीसरी लाइन तथा गोरखपुर-नकहा जंगल की दूसरी लाइन का शिलान्यास किया गया.

गोरखपुर स्टेशन पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि सांसद महंत योगी आदित्यनाथ ने समारोह का शुभारम्भ दीप प्रज्ज्वलित कर किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गोरखपुर एवं आसपास के क्षेत्र की जनता की मांग को पूरा करने हेतु अब तक चल रही साप्ताहिक ट्रेन को प्रतिदिन कर दिया गया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेलमंत्री सुरेश प्रभु द्वारा गोरखपुर को इतनी सारी परियोजनाएं प्रदान करने के लिए साधुवाद दिया. उन्होंने कहा कि महाप्रबंधक राजीव मिश्र के नेतृत्व में सर्वाधिक योजनाएं पूर्वोत्तर रेलवे को मिली हैं.

उन्होंने कहा कि आगामी तीन-चार वर्षों में गोरखपुर का विभिन्न स्तरों पर विकास होगा, जिसमें भारतीय रेल अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी. उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय में कोई योजना रखने पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक का सकारात्मक रूख रहता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कई तरह के विकास कार्य हो रहे हैं. यह विकास पूर्वी उत्तर प्रदेश पर रेलवे में भी हो रहा है. उन्होंने गोरखपुर से इलाहाबाद के लिए इंटरसिटी चलाने की मांग तथा नंदानगर में अंडरपास बनाने की मांग की. श्री योगी ने चिल्लूपार के विधायक राजेश त्रिपाठी की यह मांग भी उठाई कि सहजनवा-दोहरीघाट होते हुए बनने वाली लाइन में चिल्लूपार को भी जोड़ा जाए.

बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर आयोजित समारोह में बोलते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने आजादी के बाद से अब तक का सबसे अधिक विकास पूर्वी उत्तर प्रदेश का किया है. इसके पूर्व, पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्र ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि गोरखपुर-बस्ती-गोंडा 151 किमी. रेल खंड का विद्युतीकरण केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन द्वारा कराया गया तथा इस कार्य को पूरा करने में कुल 263 करोड़ रुपए की लागत आई है. 26 अगस्त, 2016 को लखनऊ-गोरखपुर-छपरा खंड पर विद्युत कर्षण से 12554 नई दिल्ली-बरौनी एक्सप्रेस को चलाया गया.

उन्होंने कहा कि बदलते परिदृष्य में निकट भविष्य में पूर्वोत्तर रेलवे पर बड़े पैमाने पर रेल गाड़ियों का संचालन विद्युत कर्षण से होगा, जिससे इलेक्ट्रिक इंजनों के अनुरक्षण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विद्युत लोको शेड की स्थापना आवश्यक हो गई थी. रेल मंत्रालय द्वारा इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए रेल बजट 2016-17 में गोरखपुर में विद्युत लोको शेड की स्थापना को 89 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया गया.

महाप्रबंधक ने कहा कि यात्री यातायात को ध्यान में रखकर गाड़ियों के संचालन के दबाव को देखते हुए डोमिनगढ़-गोरखपुर-गोरखपुर कैंट-कुसुम्ही (15.6 किमी.) तीसरी लाइन एवं गोरखपुर-नकहा जंगल (5.6) दूसरी लाइन निर्माण को रेल बजट 2016-17 में 186 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृति प्रदान की गई है. डोमिनगढ़-गोरखपुर-गोरखपुर कैंट-कुसुम्ही खंड पर वर्तमान में दोहरी लाइन है. गोरखपुर-नकहा जंगल इकहरी लाइन खंड घनी आबादी वाला क्षेत्र है. रेल यातायात में वृद्धि के फलस्वरूप दूसरी लाइन की व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक हो गई है.

समारोह में धन्यवाद ज्ञापन मंडल रेल प्रबंधक, लखनऊ आलोक सिंह ने किया तथा संचालन मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने किया.

# समस्या पैदा करना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के समान है...

**पेज 5 का शेष...** पालन हो, इसमें कमोवेश रेलवे बोर्ड भी उनका सहायक बना हुआ है. उन्होंने कहा कि समस्या पैदा करना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के समान है. उन्होंने कहा कि मंत्री ने हर महीने मीटिंग करने के लिए डीजी से कहा था, मगर अब एजेंडा मांगा जा रहा है. एसोसिएशन ने जब कहा कि एजेंडा 12 साल से सौंपा हुआ है, उसी एजेंडे पर बात करनी है, तब से चुप्पी साधकर बैठ गए हैं. रिस्ट्रक्चरिंग का मामला वित्त मंत्रालय भेजे जाने का कोई औचित्य नहीं था, यह सिर्फ परेशान करने और ज्यादा गालियां खाने वाला काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जबकि उसे बखूबी मालूम है कि रिस्ट्रक्चरिंग को वह रोक नहीं सकता है, एक न एक दिन उसे देना ही पड़ेगा, मगर सरकार का नुकसान करवाकर और गालियां खाकर देने से तो शराफत से देना ज्यादा अच्छा होता है. उन्होंने कहा कि जानवर से बचने के लिए घर बनाकर अपनी सुरक्षा के इंतजाम करके आदमी जानवर से तो सुरक्षित हो गया, मगर अब जब उसके अंदर ही जानवरों वाली प्रवृत्ति पैदा हो गई है, तब जानवर से भी ज्यादा खूंखार हो चले आदमी को आदमी से कौन सुरक्षित करेगा?

इसके बाद सभी जोनल पदाधिकारियों ने एक-एक करके अपने जोनों में प्रशासन और एसोसिएशन की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बैठक को अवगत कराया. सभी वक्ताओं ने जोन के स्तर पर भर्ती और आरपीएसएफ का विलय किए जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया. इसके साथ ही उन्होंने आरपीएसएफ में महिला वाहिनी के औचित्य पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा किया. उनका कहना था कि जिस तरह पुरुष आरपीएसएफ जवानों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसी प्रकार महिला आरपीएसएफ कर्मियों का भी किया जाने लगे, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी. उन्होंने ट्रेस पासिंग के लक्ष्य को खत्म करने की भी मांग की और कहा कि 'टारगेट' के चक्कर में कई बार गरीबों और बेकसूर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है.

द.पू.रे. के महामंत्री प्रमोद कुमार ने शालीमार को पूर्ण आरपीएफ डिवीजन का दर्जा देकर वहां डीएससी स्तर के अधिकारी को पदस्थ किए जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि इससे वहां के स्टाफ को सौतेले व्यवहार से निजात मिलेगी और रेलवे की पर्याप्त आय भी बढ़ेगी. उनका यह भी कहना था कि रिस्ट्रक्चरिंग से सरकार को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, जबकि 650 से कुछ ज्यादा लोगों को

इसका प्रमोशनल लाभ मिलेगा और अखिल भारतीय स्तर पर 7500 आरपीएफ कर्मियों को इससे लाभ मिलने वाला है. सिर्फ 176 लोगों को ही रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ मिल रहा है. उन्होंने कहा कि आरपीएफ में ट्रेनिंग रिज़र्व नहीं रखा जाता है, इसके साथ ही नियमानुसार कुल रिक्तियों का भी 2.5% रिज़र्व होना चाहिए. इस तरह कुल 5% रिज़र्व होना चाहिए. उन्होंने कहा कि लंबे समय से रेल प्रशासन यार्ड स्टिक नहीं बना पा रहा है.

वक्ताओं ने कहा कि जन-प्रतिनिधियों को भी रेलवे में रोजाना चलने वाले तीन करोड़ रेलयात्रियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व लेना चाहिए. पर्याप्त संख्या में एमिनिटी स्टाफ उपलब्ध कराया जाना चाहिए. उन्होंने प्रमोशन में परीक्षा और टीए की सीमा खत्म किए जाने तथा आरपीएफ बैरक्स में साफ-सफाई और कैंटीन का बंदोबस्त आउटसोर्स किए जाने की भी मांग की. सभी वक्ताओं ने आरपीएसएफ को गैर-कानूनी बताया. उन्होंने कहा कि आरपीएसएफ को बनाए रखने का मतलब गुलामी की प्रथा की जारी रखने के समान है. पूर्वोत्तर रेलवे के पदाधिकारियों ने सीएससी की मनमानी और स्टाफ के गैर-इस्तेमाल की बात कही. उन्होंने कहा कि दिल्ली में 25 लोगों को अनावश्यक रूप से अटैच करके रखा गया है. उनका कहना था कि दिल्ली और नई दिल्ली में 6 बटालियनें 20-25 सालों से एक ही जगह नियुक्त हैं, इसी प्रकार कोलकाता, दानापुर आदि में भी यह बटालियनें रखी गई हैं, जबकि नियमानुसार यह 15 दिन से ज्यादा एक जगह पर नहीं होनी चाहिए. दोनों दिन बैठक का संचालन राष्ट्रीय अध्यक्ष एस. आर. रेड्डी ने किया. जबकि इस बार राष्ट्रीय महामंत्री यू. एस. ने सभी जोनल पदाधिकारियों की अलग से क्लास ली और उनके यहां चल रहे आपसी मनमुटाव शीत उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान किया और एकजुट होकर संगठन को मजबूत ब्बनाए जाने पर जोर दिया. इसी परिप्रेक्ष्य में दो जोनल पदाधिकारियों को एसोसिएशन के विरुद्ध उनकी गतिविधियों के लिए उन्हें 6-6 साल के लिए एसोसिएशन की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया. इस मौके पर पुखरायां रेल दुर्घटना में मारे गए 154 निर्दोष रेलयात्रियों और ड्यूटी के दौरान शहीद हुए कई आरपीएफ कर्मियों को दो मिनट का मौन रखकर उनकी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और राष्ट्रगान के साथ बैठक का समापन हुआ.

# गोमतीनगर स्टेशन का सुनियोजित तरीके से होगा विकास

गोरखपुर ब्यूरो, लखनऊ : केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह एवं रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने लखनऊ के गोमतीनगर स्टेशन परिसर में आयोजित समारोह में प्रवेश द्वार, इलाहाबाद मंडल कार्यालय (उत्तर मध्य रेलवे) में एक मेगावाट सोलर पावर पैनलों का एवं उत्तर मध्य रेलवे में 7 एस्केलेटरों एवं 30 लिफ्टों, लखनऊ स्टेशन

## गृहमंत्री एवं रेलमंत्री ने लखनऊ की विभिन्न नवनिर्मित रेल स्थापनाओं का उद्घाटन किया

(उत्तर रेलवे) यार्ड के 4 लाइन प्रवेश/निकास एवं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्यों का तथा 4 एस्केलेटरों एवं 5 लिफ्टों एवं गोमतीनगर टर्मिनल के प्रथम चरण के कार्यों का उदघाटन, लखनऊ जं. (पूर्वोत्तर रेलवे) के प्लेटफार्म सं.6 पर एस्केलेटर एवं उन्नत यात्री सुविधाओं, लखनऊ-दिलकुशा-बाराबंकी खंड (उ.रे.) पर गोमती नदी पर पुल सं.469 एवं लखनऊ स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर पूर्ण रूपेण एलईडी द्वारा प्रकाश व्यवस्था का लोकार्पण एवं गोमतीनगर टर्मिनल (पूर्वोत्तर रेलवे) के द्वितीय चरण के कार्यों एवं ऐशबाग और डालीगंज स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) के द्वितीय प्रवेश द्वार तथा लखनऊ सिटी (पूर्वोत्तर रेलवे) का शिलान्यास फलक अनावरण किया.

समारोह को संबोधित करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रेल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास में विशेष योगदान देने के लिए मैं रेलमंत्री सुरेश प्रभु को



हार्दिक धन्यवाद देता हूं. उन्होंने कहा कि श्री प्रभु दूरदर्शी व्यक्ति हैं, जिनकी सोच का परिणाम है कि भारतीय रेल उत्तम परिणाम देने वाली सभी इकाईयों में सबसे सर्वोत्तम है. उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर हाई स्पीड वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे यात्री गाड़ियों की प्रतीक्षा के दौरान लाइव वीडियो देख सकते हैं. हैवी डाउन लोडिंग और कार्यालयीन कार्य कर सकते हैं. लखनऊ स्टेशन से अब तक 250 गाड़ियों का संचलन होता है तथा ट्रेन पकड़ने के लिए लखनऊ के चारबाग स्टेशन जाना पड़ता है. अब गोमतीनगर स्टेशन को टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकसित हो जाने पर, यात्री यहां से गाड़ी पकड़ सकेगें, इससे लखनऊ स्टेशन पर भीड़ का दबाव कम होगा. गृहमंत्री श्री सिंह ने कहा कि लखनऊ का विकास सुनियोजित तरीके से करने के लिए प्रयास किया जा रहा है. गोमतीनगर टर्मिनल को विश्वस्तरीय स्टेशन बनाया जाएगा. बाघ एक्सप्रेस का गोमतीनगर स्टेशन पर ठहराव प्रदान किया जाएगा तथा आलमनगर (उत्तर रेलवे) को 'सैटेलाइट स्टेशन' के रूप में विकसित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मैं इन सभी विकास कार्यों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई को समर्पित करता हूं.

समारोह को संबोधित करते हुए रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेलवे ही जनता के आवागमन का मुख्य साधन है. अतः रेलवे में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के विकास को प्राथमिकता दी. इसकी आवश्यकता को देखते हुए सुधार के पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं. सभी लम्बित परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष रेलवे में 1.21 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है. बिहार में दो इंजन कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं. गोमतीनगर स्टेशन को सुनियोजित तरीके से विकसित किया जाएगा.

श्री प्रभु ने कहा कि गोमतीनगर स्टेशन के लिए आधुनिक डिजाइन बनाई जा रही है, ताकि टर्मिनल स्टेशन का निर्माण पूरा होने पर रेल यात्री तथा देशी-विदेशी पर्यटकों को यहां आने पर सुखद अनुभूति हो. उन्होने कहा कि गाड़ियों एवं स्टेशनों की स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जा रहा है. यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी फंड बनाया जाएगा. समारोह को संबोधित करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने गोमतीनगर स्टेशन को विकसित किए जाने हेतु गृहमंत्री एवं रेलमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया.

उत्तर मध्य रेलवे के इलाहाबाद एवं कानपुर के विभिन्न रेलवे इमारतों की छतों पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर 8 करोड़ रुपए की लागत से एक मेगावॉट सोलर पावर पैनल लगाए जाएंगे. इसके साथ ही 9 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न स्टेशनों पर 30 लिफ्ट तथा 4.55 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशनों पर 7 एस्केलेटर लगाए जाएंगे. इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्र, उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अरुण सक्सेना और उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ए. के पुठिया सहित पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे एवं उत्तर मध्य रेलवे के सभी वरिष्ठ रेल अधिकारियों, कर्मचारियों सहित भारी संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित थी.

## अगस्त क्रांति में टीओटी के 28 मामले पकड़े गए

**मुंबई :** पश्चिम रेलवे के सीसीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली जाने वाली गाड़ी सं.12953 अगस्तक्रांति राजधानी में ट्रांसफर ऑफ टिकट (टीओटी) के 28 मामले पकडे हैं. यह घटना शुक्रवार, 16 दिसंबर की रात की है. प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण मुंबई के एक नामी स्कूल के छात्रों की एक टीम स्टडी टूर पर दिल्ली जा रही थी. सूरत स्टेशन के बाद जब सीसीएम स्क्वाड के तीन लोग गाड़ी की चेकिंग करने लगे, तभी उन्हें एक एसी3 कोच में छात्रों की यह टीम मिली. जांच करने पर पता चला कि कुल 28 छात्र टीओटी पर यात्रा कर रहे हैं. जांच टीम ने उन्हें और उनके अध्यापकों को पेनाल्टी भरने को कहा, तो वह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित बड़े-बड़े संपर्कों का हवाला देने लगे. बताते हैं कि इनमें से एक बड़े ओहदेदार का फोन भी जांच टीम के पास आया. मगर जब जांच टीम ने उससे कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है और इसकी रिपोर्ट कमर्शियल कंट्रोल सहित रेलवे के उच्च अधिकारियों तक को भेज दी गई है, इसलिए पेनाल्टी तो भरनी पड़ेगी. परंतु पता चला कि छात्रों के अभिभावकों के पास पर्याप्त पैसा नहीं था. अभिभावकों ने कहा कि पेनाल्टी का पैसा मुंबई सेंट्रल में उनका आदमी ले जाकर जमा करा देगा. इस पर बताते हैं कि जांच टीम ने अपने उच्च अधिकारियों से बात की और मुंबई सेंट्रल में पैसा जमा कराने को कहा. रात करीब 2.30 बजे कुल 1 लाख 54 हजार रुपए से कुछ ज्यादा की राशि जमा कराई गई. इसके बाद गाड़ी में उक्त 28 टीओटी की रसीद बनाई गई. भारतीय रेल का यह शायद पहला मामला होगा, जिसमें पेनाल्टी की राशि गाड़ी के प्रस्थान स्टेशन पर जमा कराई गई और पेनाल्टी रसीदें चलती गई में बनाई गईं. जांच टीम में सीटीआई शैलेंद्र सिंह क्षत्रिय, टीटीई वासु मलगी और अविनाश शिखरे शामिल थे. इस मामले की पुष्टि पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रवीन्द्र भाकर ने की है. उल्लेखनीय है कि 'रेलवे समाचार' को इस मामले की खबर अगले दिन सुबह ही मिल गई थी, जिस पर ट्वीट करके रेलमंत्री, महाप्रबंधक/प.रे., सीसीएम/प.रे. और जांच टीम को 'रेलवे समाचार' ने बधाई दी थी.

# विकास कार्यों की समीक्षा बैठक

**गोरखपुर ब्यूरो :** महाप्रबंधक राजीव मिश्र की अध्यक्षता में पूर्वोत्तर रेलवे पर चल रही विकास परियोजनाओं और उनके कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन मंगलवार, 20 दिसंबर, 2016 को महाप्रबंधक सभागार में किया गया. बैठक में अपर महाप्रबंधक एस. एल. वर्मा सहित सभी विभाग प्रमुख, तीनों मंडलों लखनऊ, वाराणसी एवं इज्जतनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक एवं अन्य वरिष्ठ रेल अधिकारी उपस्थित थे. बैठक में महाप्रबंधक राजीव मिश्र ने पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों मंडलों में चल रहे विकास कार्यों की मदवार समीक्षा करते हुए कार्यों में अब तक की हुई प्रगति का आकलन किया. उन्होंने विभिन्न कार्यों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए शेष कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया. महाप्रबंधक ने यात्री सुविधा के क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों को हरहाल में निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए निर्देशित किया.

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2016-17 में पूर्वोत्तर रेलवे को विकास कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का समुचित उपयोग किया जाए. श्री मिश्र ने विभिन्न प्लान हेड के अंतर्गत आवंटित राशि में किए गए कार्यों की समीक्षा की तथा जिन मदों में धनराशि की कमी हो, उसमें धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया. उन्होंने गोरखपुर स्टेशन के आइलैंड प्लेटफार्मों पर लिफ्ट लगाने को कहा, जिससे अशक्त एवं विकलांग यात्रियों को कठिनाई न हो. महाप्रबंधक ने पूर्वोत्तर रेलवे के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर निर्माणाधीन द्वितीय प्रवेश द्वार, एकीकृत सुरक्षा प्रणाली, ऑनलाइन आरक्षण चार्ट सिस्टम, स्वचालित सीढ़ी, लिफ्ट, यात्रियों को बैठने हेतु बेंच, प्रतीक्षालय, शौचालय, पीने के पानी, समुचित प्रकाश व्यवस्था तथा यात्री सुख-सुविधा से जुड़े अन्य कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरा करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया. महाप्रबंधक ने अनुपयोगी समपार फाटकों को बंद करने तथा अनुपयोगी समपारों को रक्षित करने के कार्यों की समीक्षा कर इस कार्य में तेजी लाने हेतु संबंधित अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए.

बैठक में लखनऊ, वाराणसी एवं इज्जतनगर के मंडल रेल प्रबंधकों ने अपने-अपने मंडलों में चल रहे विकास कार्यों की हुई प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत किया तथा कार्य सम्पादन में आने वाली कठिनाईयों से महाप्रबंधक को अवगत कराया.

आजीवन सदस्यता 3000 रु.
संरक्षक सदस्यता 5000 रु.
कृपया चेक/डीडी 'सोहम पब्लिकेशन' के नाम निम्नलिखित संपादकीय कार्यालय के पते पर भेजें.

परिपूर्ण रेलवे समाचार
रेलवे का दोस्त, यात्रियों का साथी

संपादकीय कार्यालय
रूम नं. 105, डॉक्टर हाउस,
पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास,
कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे (महाराष्ट्र)
मोबाइल नं. 09869256875

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक **सुरेश त्रिपाठी** द्वारा सोहम पब्लिकेशन, 105, डॉक्टर हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे (महाराष्ट्र) से मुद्रित एवं 105, डॉक्टर हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे (महाराष्ट्र) से प्रकाशित.

संपादक - सुरेश त्रिपाठी

- इलाहाबाद : उमेश शर्मा ☎ 094155 08625
- गोरखपुर : विजय शंकर ☎ 09935266331
- भुसावल : शेख सत्तार ☎ 09370615244
- रतलाम : मुकेश सिंह ☎ 09427484069
- वड़ोदरा : विजय नायर ☎ 09824016464

कानूनी सलाहकार
* एड. एम. एस. ठक्कर, कल्याण,
* एड. प्रकाश ताहिलरामानी, मुंबई,
* एड. राजेश मुधोलकर, ठाणे,
* एड. कमलेश त्रिपाठी, रायबरेली,
* एड. बी. एच. वास्वानी, भोपाल,
* एड. एम. पी. दीक्षित, पटना.

किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद का न्यायिक क्षेत्र कल्याण होगा.

RNI Regd. No. MAHHIN/2002/10618
POST Regd. No. Tech/47-1542/MBI/2015-2017